एक साल कश्मीर खुशहाल

विशेषांक

वर्ष : 2, अंक : 18 | 5 अगस्त, 2020

PERFORM INDIA
National Movement for Developed India

भारत के लिए 05 अगस्त, 2019 का दिन ऐतिहासिक बन गया। इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साहसिक फैसलों ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-ए को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जम्मू-कश्मीर को विभाजित कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय न सिर्फ अप्रत्याशित और अविश्वसनीय था, बल्कि अकल्पनीय भी था। इसने एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का 66 साल पुराना सपना साकार कर दिया।

मोदी सरकार कश्मीर पर एक साथ चार बहुत बड़े फैसले करेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कदम से विपक्ष को भी अचंभे में डाल दिया। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के लिए यह बड़ा झटका था। इनमें से कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि जम्मू-कश्मीर एक राज्य से केंद्र शासित क्षेत्र बन जाएगा, जिसके साथ उनका सियासी रसूख ही समाप्त हो जाएगा।

खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए कश्मीर का मुद्दा उनके दिल के काफी करीब रहा था। इस मुद्दे का समाधान कर वे देश के इतिहास में एक ऐसी शख्सियत के तौर पर स्थापित हो गए हैं, जो लीक से अलग हटकर बड़े फैसले लेने में चूकते नहीं हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इस छवि को मजबूती मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी निर्णायक हैं और बड़े फैसले ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद से भारत को देखने के विश्व के नजरिये में बदलाव आया है। उन्होंने भारत को बार-बार पाकिस्तान से जोड़कर देखे जाने की वैश्विक सामरिक रणनीति से भी आजाद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान और चीन की हर चाल को नाकाम किया। आज पाकिस्तान को खुद मानना पड़ रहा है कि विश्व में उसकी कोई नहीं सुनता।

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के लोगों को राष्ट्रीय और भावनात्मक एकात्मकता की अनुभूति से रोकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मनोवैज्ञानिक बाधा को हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब सियासी सोच और हालात में भी बदलाव आया है। स्वार्थी नेताओं, अलगाववादियों और आतंकियों को समर्थन नहीं मिल रहा है। युवा पीढ़ी अब मुख्यधारा में शामिल होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहती है।

अनुच्छेद 370 के हटने के बाद सभी कानून जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी लागू हो गए हैं। अब सभी केंद्रीय योजनाएं केन्द्र सरकार की निगरानी में लागू हो रही हैं, जिनका सीधा फायदा राजनीतिक नेताओं को न मिलकर आम जनता को मिल रहा है। मोदी सरकार जनता और युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नए-नए कदम उठा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार है।

PERFORM INDIA
National Movement for Developed India

अनुच्छेद 370

मोदी सरकार में पहली बार

- मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया।
- मोदी सरकार में एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का सपना साकार हुआ।
- मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित किया।
- किसी राज्य को पहली बार दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।
- क्षेत्रफल के लिहाज से जम्मू-कश्मीर देश का पहला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
- जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल पद था, लेकिन अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उप-राज्यपाल का पद बनाया गया है।
- जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल की जगह अब 5 साल का होगा।
- अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भी बाकी सारे अधिकार मिल गए।
- जम्मू-कश्मीर में 15 साल से रहने वाले और 10 वर्षों की कुल अवधि तक सेवा करने वाले कर्मचारी अधिवास के पात्र होंगे।
- भारतीय मौसम विभाग ने PoK के गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताना शुरू किया।
- आजादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 24 अक्टूबर, 2019 को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए।

समस्या-समाधान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

"हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर-भीतर अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाने का काम संसद के दोनों सदनों ने दो-तिहाई बहुमत से कर दिया।"

"ये कदम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को मुख्यधारा में लाएंगे, साथ ही उन्हें कौशल और प्रतिभा प्रदर्शित करने के अनगिनत अवसर मिलेंगे। इससे वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, व्यापार-उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और आपसी दूरियां मिटेंगी।"

"मैं जम्मू-कश्मीर की बहनों और भाइयों के साहस और जज्बे को सलाम करता हूं। वर्षों तक कुछ स्वार्थी तत्वों ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग का काम किया, लोगों को गुमराह किया और विकास की अनदेखी की। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब ऐसे लोगों के चंगुल से आजाद है। एक नई सुबह, एक बेहतर कल के लिए तैयार है!"

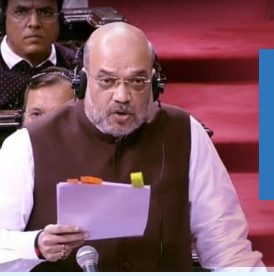

अप्रत्याशित और अकल्पनीय

◈ मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर एक साथ चार बड़े फैसले लेकर सभी अनुमानों को ध्वस्त कर सबको हैरान कर दिया।

फैसला नंबर 1- जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाना

फैसला नंबर 2 - राज्य का विभाजन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित क्षेत्र बनाना

फैसला नंबर 3 - जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र के लिए विधायिका का प्रावधान करना

फैसला नंबर 4 - लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाना

◈ राज्यसभा में एनडीए को बहुमत न होने के बावजूद दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से अनुच्छेद-370 व 35ए को हटाया गया।

◈ विपक्षी दलों के सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया।

◈ मोदी सरकार ने 66 साल बाद अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पूरा किया।

"जम्मू-कश्मीर क्या, भारत क्या, दुनिया क्या.. किसी भी कोने में कितना भी अक्लमंद आदमी रहा हो... कश्मीर का कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, उसने भी यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि एक साथ चार चीजें गृह मंत्री सदन में लाएंगे, उस पर चर्चा होगी और उसी दिन पास भी करेंगे।"

गुलाम नबी आजाद (राज्यसभा में नेता विपक्ष)

पीओके हमारा

- मोदी सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) पर बड़ा दावा करते हुए वहां के मौसम का हाल बताने का फैसला किया।
- भारतीय मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी शामिल कर लिया।
- 5 मई, 2020 से गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है।
- इस बदलाव के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान समेत उसका साथ देने वालों के लिए तीन बड़ा और सख्त संदेश दिया है।
  1. पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के 86 हजार स्क्वायर किलोमीटर पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।
  2. चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिसका भारत लगातार विरोध करता है।
  3. भारत ने एक मैसेज ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नेताओं को भी दिया।

चुनौतियां

- फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में से किसी को इस तरह के फैसलों का अंदाजा नहीं था।
- ऐसा माहौल बनाया गया था कि मानो कश्मीर को उसके स्पेशल स्टेटस से कभी बेदखल किया ही नहीं जा सकता।

"देखते हैं वे धारा 370 को कैसे खत्म करेंगे। अल्लाह कसम खाता हूं कि अल्लाह को यही मंजूर होगा कि हम इनसे आजाद हो जाएं। करें हम भी देखते हैं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा।"

फारूक अब्दुल्ला (8 अप्रैल, 2019)

"भाजपा वाले कहते हैं, हम अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाएंगे। मोदी साहब, अमित शाह साहब मैं आज आपको हंदवारा की जमीन से चैलेंज करता हूं, नहीं हटा पाएंगे। इस रियासत के लोग आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे।"

उमर अब्दुल्ला (9 अप्रैल, 2019)

"आग से न खेलें, 35-ए से छेड़छाड़ न करें। अगर ऐसा हुआ तो वो देखेंगे जो 1947 से अब तक नहीं हुआ। अगर इस पर हमला किया जाता है तो मैं नहीं जानती कि जम्मू कश्मीर के लोग कौन सा झंडा पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे।"

महबूबा मुफ्ती (25 फरवरी, 2019)

"संविधान की धारा 370 से हमें विशेष दर्जा मिला है। अनुच्छेद 35-ए सुप्रीम कोर्ट में है और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अगर इसमें बदलाव होता है तो जो कश्मीर में इतने खतरों को झेलते हुए देश के तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं, वे वहां नहीं रुकेंगे और इसके बाद तिरंगे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। इस धारा में किसी तरह के हेरफेर को मंजूरी नहीं दी जाएगी।"

महबूबा मुफ्ती (29 जुलाई, 2017)

सियासी करवट

- जम्मू-कश्मीर की मुख्यधारा की पार्टियां और अलगाववादी भी मानने लगे हैं कि उनके लिए परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं।
- जम्मू और कश्मीर के बाकी भारत के साथ रिश्तों को लेकर सारी अस्पष्टता खत्म हो चुकी है।
- फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी के खिलाफ कोई कश्मीरी सड़क पर नहीं उतरा।
- अब्दुल्ला परिवार के सियासी वर्चस्व और राजनीतिक ताकत को नुकसान पहुंचा है।
- अलगाववादियों और जमात-ए-इस्लामी पर हुई कार्रवाई के चलते पीडीपी की कमर टूट चुकी है।
- पीडीपी में बहुत कम लोग अब महबूबा मुफ्ती के भारत-विरोधी राजनीति के साथ रहना चाहते हैं।
- हुर्रियत के लोग भी मामने लगे हैं कि युवा पीढ़ी अब मुख्यधारा में शामिल होना चाहती है।
- अब लोग समझने लगे हैं कि पाकिस्तानी फंडिंग पर चले अलगाववाद से कश्मीरी समाज को मदद नहीं मिली है।
- आज दूसरी और तीसरी पीढ़ी के अलगाववादी कश्मीर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं।
- मुख्यधारा की पार्टियों के कमजोर पड़ने से ऊर्जावान और प्रगतिशील कश्मीरी युवा बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं।
- अक्टूबर 2019 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीडीसी चुनाव में 98 प्रतिशत मतदान सियासी करवट का परिचायक है।

अलग पड़े अलगाववादी

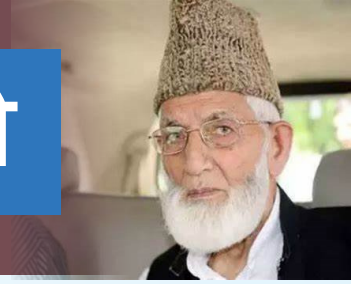

- अनुच्छेद 370 हटने के बाद अलगाववादियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है।
- गिलानी को अनुच्छेद 370 के विरोध में प्रदर्शन के लिए स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिला।
- घटते जनाधार से परेशान सैयद अली शाह गिलानी ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया।
- अनुच्छेद 370 के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाने से नाराज पाकिस्तान ने भी हुर्रियत से हाथ खींच लिया।
- 2018 में 58, 2019 में 70 और 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई।
- 2019 में प्रतिबंधित जमात ए इस्लामी के 29 कार्यकर्ता और 2020 में इसके 8 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए।
- अलगावादियों के 82 बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई है। आसिया आंद्राबी का मकान कुर्क किया गया।
- सितंबर 2019 में मसूद अजहर, हाफिज़ सईद, जाकि-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित किया गया।

"जब नई दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर को अपने संघ में मिला लिया और इसे दो भागों में विभाजित किया, तो हमारे जो नेता जेलों में नहीं थे; उनसे लोगों का मार्गदर्शन करने और नेतृत्व करने की उम्मीद थी। मैंने आपको खोजा, संदेशों के माध्यम से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। आप नहीं मिल सके।"

सैयद अली शाह गिलानी

(सहयोगियों को लिखे पत्र का अंश)

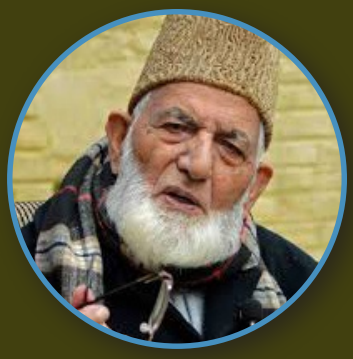

पाकिस्तान पस्त

- मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र से लेकर सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को मात दी।
- UNSC में जम्मू-कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान की हर चाल को भारत ने नाकाम किया।
- UNSC ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे को मीटिंग एजेंडा में शामिल करने के पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया।
- कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के लिए पाकिस्तान इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी की बैठक तक नहीं बुला सका।
- यूएई जैसे पाकिस्तान के हितैषी कई मुस्लिम देशों ने भारत का आंतरिक मामला बताकर अपने को अलग कर लिया।
- जनवरी 2020 में पीएम इमरान खान ने माना कि कश्मीर मुद्दे पर उन्हें वैश्विक समुदाय का साथ नहीं मिल रहा।

"दुर्भाग्यवश, पश्चिमी देशों के लिए व्यावसायिक हित ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। भारत बड़ा बाजार है और कश्मीर में 80 लाख लोगों के साथ क्या हो रहा है, उस पर धीमी प्रतिक्रिया की यही वजह है।"

इमरान खान (पाकिस्तान के प्रधानमंत्री)

" पिछले छह सालों में भारत बदला है और मुझे डर है कि वह ज्यादा तेजी से बदलने जा रहा है। इसलिए मैं इसे तुष्टिकरण कहता हूं। दुनिया को कोई रुख तय करना होगा।"

इमरान खान (पाकिस्तान के प्रधानमंत्री)

''हम कहते हैं कि उन्होंने (भारत) कर्फ्यू लगा दिया, वहां दवाईयां नहीं मिल रहीं, लेकिन लोग (दुनिया) हम पर भरोसा ही नहीं कर रहे, बल्कि वे तो भारत पर भरोसा कर रहे हैं।''

एजाज अहमद शाह (इमरान खान सरकार में गृह मंत्री)

बदला नजरिया

- पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले का समर्थन दुनिया भर में किया गया।
- अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, यूएई, इजरायल समेत विश्व के तमाम छोटे-बड़े देशों ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया।
- मोदी सरकार ने भारत को बार-बार पाकिस्तान से जोड़कर देखे जाने की वैश्विक सामरिक रणनीति से भी आजाद कर दिया।
- पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाकर कश्मीर मामले में विश्व का नजरिया ही बदल दिया।
- यूरोपियन आयोग के पूर्व निदेशक ब्रायन टोल ने कहा कि कश्मीर में लोगों को सामान्य रूप से आर्थिक अवसर मिलेंगे।
- फरवरी 2020 में मौके पर जाकर आकलन करने के उद्देश्य से 25 विदेशी राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंचा।
- जनवरी 2020 में 15 विदेशी राजनयिकों का दल जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गया था।
- अक्टूबर 2019 में यूरोपीय संसद के 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भी कश्मीर का दौरा किया था।

राज्य पुनर्गठन

- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन से संबंधित प्रावधानों को औपचारिक रूप से 31 अक्टूबर, 2019 को लागू किया गया।
- जम्मू-कश्मीर राज्य को विभाजित कर दो केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में पुनर्गठित किया गया।
- राज्य के 354 कानूनों में से 164 कानूनों को निरस्त किया गया, 138 कानूनों को संशोधित किया गया।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर 170 केंद्रीय कानून लागू किए गए।
- जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को भूमि अधिग्रहण के लिए अब NOC की ज़रूरत नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

वंचित को लाभ

- नई अधिवास परिभाषा के अनुसार 15 वर्ष या अधिक समय तक जम्मू-कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति अधिवासी माने जाएंगे।
- वाल्मीकी समुदाय के लाखों लोग अब जम्मू-कश्मीर के नागरिक बन गए हैं।
- पश्चिमी पाकिस्तान से उजाड़े और खदेड़े गए शरणार्थियों को भी उनके मानवीय और नागरिक अधिकार मिल गए हैं।
- 1990 और उसके बाद कश्मीर घाटी से भगाए गए कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने का रास्ता साफ हो गया है।
- जम्मू-कश्मीर से बाहर विवाह करने वाली लड़कियों और उनके बच्चों के अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है।

विकास का विस्तार

- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास को लेकर रोडमैप तैयार करने के लिए एक मंत्री समूह (GoM) का गठन किया गया है।
- मोदी सरकार के 36 मंत्रियों ने18-25 जनवरी,2020 के बीच जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाकों का दौरा किया।
- केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने गंदेरबल में 20 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
- 40 वर्ष से रूकी हुई शाहपुर-कंडी बांध परियोजना पर कार्य शुरू किया गया है।
- जम्मू-कश्मीर में दो एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। इनमें से एक एम्स जम्मू में होगा और दूसरा कश्मीर में।
- मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में नौ मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है।
- 25 अगस्त,2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 85 विकास योजनाओं की शुरुआत की।
- 80,068 करोड़ रुपये वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत विकास परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- मोदी सरकार ने लद्दाख में बौद्ध अध्ययन केंद्र के साथ पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की योजना को हरी झंडी दी।
- मोदी सरकार रोजगार और युवकों के कौशल विकास पर समान रूप से ध्यान दे रही है।
- एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान पुस्तक के एक पाठ में अनुच्छेद 370 हटाने का विषय जोड़ा है।
- आज़ादी के बाद पहली बार जुलाई 2020 में उत्तरी कश्मीर में LoC से सटे केरन, मुंदियां और पतरू गांवों में बिजली पहुंची।

65 साल का सपना साकार

- लद्दाख के स्थानीय निवासी केंद्र शासित प्रदेश बनाये जाने से काफी खुश हैं।
- लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए महान नेता कुशोक बकुला के नेतृत्व में 65 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ।
- लद्दाख के एक अन्य नेता थूपस्तान चवांग ने इसे आगे बढ़ाया।
- 2019 में लद्दाख का बजट 57 करोड़ रुपये था, जो 2020 में चार गुना बढ़कर 232 करोड़ रुपये हो गया।
- लद्दाख को विशेष विकास पैकेज के रूप में 6000 करोड़ रुपये का बजट मिला है।

फिर चमकेगा पर्यटन

- जम्मू -कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है।
- उन जगहों की पहचान की जा रही है, जो टॉप के टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकते हैं।
- मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के टूरिस्ट गाइड को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देगी।
- हिमालय की 137 पर्वत चोटियां विदेशी पर्यटकों के लिए खोली गई हैं, जिनमें 15 चोटियां जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की हैं।

आतंक पर शिकंजा

- पिछले एक साल में आतंकी संगठनों में कश्मीरी युवाओं की भर्ती में 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
- जनवरी से 15 जुलाई, 2019 तक 105 युवा आतंकी संगठनों में शामिल हुए, वहीं इस साल इसी अवधि में इनकी संख्या 67 थी।
- जनवरी से 15 जुलाई, 2019 तक आतंकवाद से जुड़ी कुल 188 घटनाएं हुईं, वहीं इस साल इसी अवधि में 120 घटनाएं हुईं।
- जनवरी से 15 जुलाई, 2019 तक 126 आतंकी मारे गए, इस साल इसी अवधि में 136 आतंकियों का खात्मा हुआ।
- इसके अलावा 22 आतंकी और करीब उनके 300 मददगार गिरफ्तार किए गए।
- इस अवधि में पिछले साल 6 IED हमले हुए, वहीं इस साल 15 जुलाई तक केवल 1 IED हमला हुआ।

इस एक साल में हिज़्बुल मुजाहिद्दीन का कमांडर रियाज़ नाइकू, लश्कर का कमांडर हैदर, जैश का कमांडर कारी यासिर और अंसार ग़ज़वात-उल-हिन्द का बुरहान कोका भी मारा गया।

पस्त हुए पत्थरबाज

- अब मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर पथराव नहीं होता है।
- 2018 में पथराव की 532 घटनाएं हुईं, वहीं 2019 में 389 और 2020 में 102 घटनाएं हुई हैं।
- 2018 के मुकाबले 2019 में पथराव की घटनाओं में 27 प्रतिशत की कमी आई, वहीं 2020 में 73 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
- पथराव की घटनाओं में 2019 में 335 नागरिक घायल हुए और इस साल केवल 63 नागरिक घायल हुए।

सेना की सख्ती

- मोदी सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ तीव्र और सख्त कार्रवाई करने के लिए सेना को खुली छूट दी।
- आतंकियों को जिंदा पकड़ने की बाध्यता खत्म कर 'खोजो और मारो' (कार्डन एंड सर्च) ऑपरेशन 'कासो' चलाया गया।
- आतंकियों के खिलाफ 'आबादी में घेरो, जंगल में मारो' की दूसरी रणनीति अपनायी गई।
- दक्षिण कश्मीर में बुरहान वानी गैंग को खत्म करने के लिए ऑपरेशन 'जैकबूट' चलाया गया।
- घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सेना की बहुस्तरीय तैनाती, बाड़ लगाने और खुफिया तंत्र की मजबूती का काम किया गया।
- घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई, जो काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

ऑपरेशन ऑल आउट

- जनवरी 2017 में शुरू किए गए ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकियों के हौसले पस्त हो चुके हैं।
- 2014 – 15 जुलाई, 2020 तक जम्मू-कश्मीर में 1126 आतंकियों को मार गिराया गया।

साल	आतंकी मारे गए
2014	110
2015	108
2016	150
2017	213
2018	257
2019	152
2020 (15 जुलाई)	136